बांग्लादेश में जारी हिंसा

*अमित रंजन, पीएच डी**

30 मार्च 2015 को एक ब्लॉगर वशिकुर रहमान की उनके प्रगतिवादी ब्लॉगों के कारण चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले एक नास्तिक ब्लॉगर अभिजीत राय की हत्या 27 फरवरी 2015 को ढाका में करवा दी गई थी। वे बांग्लादेश में जन्मे अमरीकी नागरिक और एक ब्लॉग *'मुक्तो मनो'* के संस्थापक थे। रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश स्थित एक इस्लामी अतिवादी समूह, अन्सारूल्ला बांग्ला टीम ने उनकी हत्या की जिम्मेवारी लेने का दावा किया। हालांकि उनकी हत्या ने विश्व का ध्यान खींचा है, पर यह विशेषकर वर्ष 2013 के बाद, बांग्लादेश में (हुई) ऐसी पहली हत्या नहीं थी। अतीत में भी अनेक लोगों की हत्या उनके (द्वारा व्यक्त) विचारों के चलते इसी अंदाज में कर दी गई थी।

कट्टरपंथी समूह अपने पुरातनपंथी विचारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की असहमति के प्रति असहिष्णु हो गए हैं, जिसे वे किसी 'शत्रु' की ओर से दी गई चुनौती मानते हैं। वर्ष 2013 में एक ब्लॉगर, राजीव हैदर ने अपने ब्लॉगों के माध्यम से लोगों को एकजुट करके वर्ष 1971 में हुई हिंसा के षडयंत्रकारियों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधीकरण-2 (आईसीटी-2) द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के बदले मौत की सजा की मांग की। उनका ब्लॉग उन (ब्लॉगों) में से एक था, जिसने शाहबाग विरोध-प्रदर्शन को हवा दी थी। परिणामस्वरूप, हैदर को *हेफ़ाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश* (एचईएल) के कार्यकर्ताओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। *हेफ़ाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश* (एचईएल) का गठन वर्ष 2010 में बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नीति के विरूद्ध विरोध-प्रर्दशन के लिए किया गया था। बाद में, इस समूह ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुई हिंसा के षडयंत्रकारियों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाले शाहबाग विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने से लोगों को रोकने के लिए हिंसक कार्रवाई की।

बांग्लादेश में जारी हिंसा की जड़ें वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में निहित हैं। पूर्वी भाग में पाकिस्तानी सेना और इसके सहयोगियों ने नागरिकों के विरूद्ध खुलकर हिंसा की और राष्ट्र के विरूद्ध बढ़ते असंतोष को कुचलने के लिए बलात्कार किए। वे लोग, जो मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी गैर-बांग्लादेशियों के विरूद्ध इसी प्रकार के साधन और तौर-तरीके अपनाए, हालांकि उत्तरवर्तियों (पाकिस्तानी सेना) द्वारा की गई हिंसा की तुलना में इसकी मात्रा बहुत कम थी। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद यह सोचा गया था कि हिंसा का स्तर घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि राजनैतिक नेतृत्व ने असंतुष्टों को दबाने के लिए एक साधन के रूप में इसका (हिंसा का) प्रयोग किया।

शेख मुजीबुर्रहमान के कार्यकाल के दौरान *जातीय रक्षा बाहिनी* (जेआरबी) का गठन मार्क्सवादी असंतुष्ट गुट, *गण बाहिनी* से लड़ने के लिए किया गया था। लेकिन इसका उद्देश्य हिंसक तरीके अपनाकर सभी असंतुष्टों को चुप कराना था। वर्ष 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद जनरल जियाउर्रहमान सत्ता पर काबिज़ हुए। उनके कार्यकाल के दौरान गुलाम आज़म को लंदन में अपने निर्वासन से वापस लौटने की अनुमति दी गई, जिन्होंने वर्ष 1971 में अनेक निर्दोष बांग्लादेशियों के विरूद्ध हिंसा करने में रजाकारों की अगुवाई की थी। यह अतिवाद की शुरूआत थी, जिसने 15 वर्ष के सैनिक शासन के दौरान स्वयं को स्थापित कर लिया। वर्ष 1991 में लोकतांत्रिक प्रणाली की पुन:स्थापना के बाद भी इसे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला।

अतिवादी समूहों और सुधारवादी गुटों के बीच वर्तमान संघर्ष का मूल कारण 1971 की उनकी व्याख्याओं में (निहित) मतभेद हैं, जो विरोधाभाषी हैं। ऐसी व्याख्या के आधार पर वे एक-दूसरे को 'शत्रु' मानते हैं। वर्ष 1971 में एक देश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद बांग्लादेश ने इनके बीच मतभेदों को कम करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। बल्कि, चुनावी फायदे के लिए विभिन्न समूहों और दलों द्वारा इन मतभेदों को भुनाया गया है। वर्ष 2009 में लोक-सम्मत मांग पर कार्रवाई करते हुए शेख हसीना के नेतृत्व में आवामी लीग की सरकार ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हिंसा करने वाले षडयंत्रकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधीकरण-2 (आईसीटी-2) का गठन किया। वर्ष 2013 से जब आईसीटी-2 ने अपना फैसला सुनाना प्रारंभ किया, तब *जमात-ए-इस्लामी* (जेआई) और इसकी छत्रछाया तले सक्रिय संगठन ने पूरे बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। इसके कार्यकर्ता पेट्रोल बम फोड़ने लगे और कतिपय महत्वपूर्ण स्थानों पर क्रूड बम तक लगा दिए गए थे।

वर्ष 1971 (के युद्ध) ने न केवल संघर्षकारियों और मुक्तिवाहकों के बीच दीवार खड़ी कर दी, बल्कि इसने पीड़ितों को भी जन्म दिया है। मुक्ति संग्राम, जो बंगाली पहचान को उचित जगह देने के लिए लड़ा गया था, उसका उपयोग (अब) एक समग्र बांग्ला पहचान की कीमत पर एक राष्ट्र के निर्माण के लिए किया जा रहा है। हिन्दुओं को उनके बंगाली पृष्ठभूमि के कारण शामिल किया गया है, लेकिन मध्य तथा पूर्वी भारत के मुसलमानों, जिन्होंने वर्ष 1947 में इस भूमि को अपना घर स्वीकार किया था, उन्हें 1971 के बाद एक राष्ट्र की संकल्पना से अलग किया जा रहा है। ऐसी संकल्पना के अभाव और राष्ट्र के बर्ताव ने इस समूह के सदस्यों को अलग-थलग कर दिया है। इस समुदाय के अधिकांश सदस्य देश भर में फैले शिविरों में रहते हैं जहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं (तक) उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ती ही है। इस समुदाय के अधिकांश सदस्य को अतिवादी बनाने में अधिकार-हनन और अलगाव ने मिलकर काम किया है। वे आसान लक्ष्य हैं, इसलिए उनका शोषण बांग्लादेश में जारी हिंसा के लिए उत्तरदायी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस समुदाय के अधिकांश सदस्य अवसरों के अभाव और स्थापित प्रणाली के विरूद्ध गुस्से के कारण हिंसक घटनाओं में लिप्त हैं। 11 मार्च, 2015 को *जमात-ए-इस्लामी* (जेआई) के सहायक महासचिव मोहम्मद कमारूजामन को फांसी दिए जाने से बांग्लादेश में हिंसा में बढ़ोत्तरी होगी और कट्टरपंथी तत्व मजबूत होंगे।

सामाजिक-राजनीतिक हिंसा पर काबू पाने के लिए राष्ट्र और सिविल सोसायटी को कतिपय प्रयास करने की आवश्यकता है: *सर्वप्रथम,* सभी को सरकारी दृष्टिकोण स्वीकार करने पर बाध्य करने की बजाए बांग्लादेश के 1971 मुक्ति संग्राम की परस्पर-विरोधी व्याख्याओं पर चर्चा तथा वाद-विवाद होने देना चाहिए। *दूसरा,* धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरवाद (की भावना) से मुक्त कराना चाहिए; और *अंत में,* राष्ट्रों को उन वित्तीय संसाधनों पर निगरानी रखनी होगी, जिन्हें विश्व भर से अतिवादी समूह प्राप्त कर रहे हैं।

***

** डॉ. अमित रंजन विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*